

प्रेषक,

एस0के0मुट्टू,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 6 जुलाई, 2010

विषय:—मै0 लिग्यांज विश्वविद्यालय ट्रस्ट नई दिल्ली को, ग्राम बंजारेवाला ग्रान्ट, परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (विश्वविद्यालय स्थापना हेतु) कुल 29.4530 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-495/भूमि व्यवस्था-भूमि कय-VIII, दिनांक-10.6.2010 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-562/XVIII(II)/2010-18(2)/2008, दिनांक-10.3.2010 को अतिक्रमित करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै0 लिग्यांज विश्वविद्यालय ट्रस्ट नई दिल्ली को, ग्राम बंजारेवाला ग्रान्ट, परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (विश्वविद्यालय स्थापना हेतु) कुल 29.4530 है0 भूमि कय की अनुमति, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-154 (2) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III)के अन्तर्गत, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति तथा आपके द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार/संस्तुत खसरा संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (तकनीकी शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं उच्च शैक्षणिक पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी



- है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।
- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 7- संस्था द्वारा भवन निर्माण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 8- संस्था द्वारा तकनीकी, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु, आवश्यक है कि वे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उनके अधीन सक्षम संस्थाओं/प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा किया जायेगा।
- 9- संस्था द्वारा प्रस्तावित भूमि का उपयोग, विश्वविद्यालय के पठन पाठन, छात्रावास/शिक्षकों एवं कार्मिकों के आवास हेतु ही किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु, भूमि का उपयोग किये जाने पर उक्त भूमि राज्य हित में स्वतः निहित कर ली जायेगी।
- 10- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो। इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 11- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 12- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 13- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 14- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, यथाशीघ्र शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(एस0के0मुट्टू)

अपर मुख्य सचिव।

प्र०प०सं०-1512/समदिनांकित/2010

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- डा० पिचेश्वर गड्डे, सचिव, लिग्याज विश्वविद्यालय ट्रस्ट, कार्यालय सी-72 द्वितीय तल, शिवालिक मालवीय नगर, नई दिल्ली।
- 6- निर्देशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 7- प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(संतोष बडोनी)  
अनु सचिव।